CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–01 | मासिक बुलेटिन | जून 2022

संपादकीय ....

एक ओर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया के रूप मे शासक वर्ग का भोंपू बन कर मेहनतकशों की रोजी–रोटी पर हो रहे हमलों को कवर करने की जगह धड़ल्ले से झूठी खबरें प्रसारित कर के शासक वर्ग के गुण–गान में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बैठे शासक वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधि देश के संविधान और लोकतंत्र को लगातार कमजोर करते हुए सांप्रदायिक धुव्रीकरण की सुनियोजित साजिश के एजेंडे को आगे बढा रहे हैं।

विरोध मे जो लोग आगे बढ़ कर भारत के संविधान और लोकतंत्र पर शासक वर्ग के सुनियोजित प्रहार का प्रतिरोध कर रहें हैं उन्हें 'देशद्रोही' और अर्बन नक्सल प्रचारित कर "गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम" (युएपीए) जैसे काले कानून का सहारा लेकर जेलों मे बंद किया जा रहा है। झारखंड में ही ऐसे हज़ारों मुक़दमे थोपे गए हैं जिनमें बहुतायत में संघर्षरत आदिवासी हैं।

आज देश की आम जनता बढती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। इन और इन जैसे प्रमुख जनमुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति मे जन–प्रतिरोध की आवाज के साथ जारी सैकड़ों जनसंघर्षो की कटु सच्चाई आम लोगों तक पहुंचाने का काम और उन संघर्षों से जुड़ने का आह्वान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। "जन जोहार" बुलेटिन का डिजिटल प्रकाशन का पहला अंक इसी काम में आगे बढा हुआ एक नन्हा कदम है। झारखंड में कारपोरेट– सांप्रदायिक ताक़तों के गठजोड़ के जहरीले प्रचार तंत्र के खिलाफ राज्य के मेहनतकशों और धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील शक्तियों के प्रतिरोध की आवाज और सही वस्तु स्थिति पेश करने के साथ–साथ आपके सुझावों के मंच के रूप में आपके अपने "जन जोहार" का प्रथम अंक आप सभी को समर्पित है। □

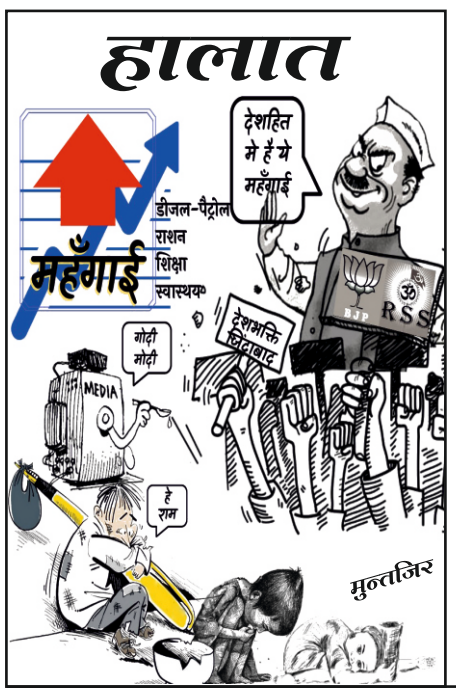

बिरसा मुण्डा शहादत दिवस

जल–जंगल–ज़मीन की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसमें मुंडा किसानों की ज़मीन पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था और ज़मीन पूरे समाज का प्राकृतिक संसाधन हुआ करती थी, को भंग कर अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा महाजनी भूमि व्यवस्था और सूदख़ोरी लागू करने के विरोध में 'अंग्रेजों अपनो देश वापस जाओ' का नारा देकर उलगुलान का नेतृत्व करने वाले बाग़ी बिरसा मुंडा को माकपा आज उनके शहादत दिवस पर गर्व के साथ नमन करता है। बिरसा मुंडा ने तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया। पहला जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनो की रक्षा, दूसरा नारी की रक्षा और सुरक्षा तथा तीसरा अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाये रखना। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर क्रांतिकारी बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आन्दोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में दो साल के कारावास की सजा दी गई।

1897 में बिरसा और उनके चार सौ साथियों ने खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई। बाद में षडयंत्र के तहत अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ़्तार कर उन पर झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। जहां उन्हें अंग्रेजों ने धीमा जहर दिया, जिससे 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हो गई। परन्तु आज भी बिरसा मुंडा जनमानस में जननायक के रूप में जीवित हैं और बाद की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। □

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हमला

विनिवेश, निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) की नीति का प्रभाव झारखंड की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है ।

बीसीसीएल के 38 खदानों को निजी हाथों में सौंपने की योजना, कोल इंडिया लिमिटेड के 204 कोयला ब्लॉकों को 2023–24 तक कोयला खनन के व्यावसायीकरण के रूप में चिह्नित करने के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपनी गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और (CMPDI) से 25–25% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। ट्रेड यूनियनों के एकजुट आंदोलनों के कारण सीएमपीडीआई को सीसीएल से अलग करने की साजिश को रोका जा सका। केंद्रीय बजट 2021 में प्रस्तावित विनिवेश योजना के तहत मेकॉन की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी है। रघुबर सरकार ने सितंबर 2014 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खनन पट्टा नवीनीकरण मुद्दे पर केंदाडीह, सूरदा खदान संचालन और इसके विस्तार परियोजना कार्य को रोक दिया था, अब निजी ठेकेदार को आउटसोर्सिंग कर खनन कार्य शुरू किया गया है। बीएसएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई होने के कारण विनिवेश के खतरे से अछूता नहीं है। मेघातुबुरु और किरीबुरु के खनन पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है और लौह अयस्क समृद्ध नए क्षेत्रों में खुदाई के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही है। विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार उतावली है। इसके अलावा एनएमपी के तहत रांची हवाई अड्डा व टाटानगर से हावड़ा के बीच एक लग्जरी ट्रेन को सौंपने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार झारखंड के गौरव एवं मातृ उद्योग के रूप में माने जाने वाले एचईसी को दोस्ताना कॉरपोरेट घराने के हाथ में सौंपने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार जानबूझकर इस विरासती पीएसयू के लिए न तो बजट आवंटित कर रही है और न ही तकनीकी उन्नयन की व्यवस्था कर रही है। इस कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने एकमुश्त 1300 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नतीजन, हज़ारों परिवारों के सामने बेकारी–भूखमरी का संकट है।

झारखण्ड में सार्वजनिक बैंकों के विलय से ब्रांचों की संख्या घटी है, एटीएम की संख्या घटी है जिससे आम आदमी तक बैंकिंग सेवा की पहुँच घटी है। वहीं दूसरी ओर झारखण्ड के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति दयनीय है और इसके पुनरूद्धार के लिये राज्य सरकार गंभीर नहीं है।

झारखंड सरकार के अनुसार भूमि मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर ₹1,01,142 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक उत्खनित खनिज की कीमत के रूप में मुआवजे के एवज में ₹ 32,000 करोड़ और ₹ 2,900 करोड़ धुले कोयले की रॉयल्टी बकाया के रूप केन्द्र के पास बकाया है।

पिछले दो दशकों से इन सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग कोई भर्ती नहीं हुई है, आउटसोर्सिंग, संविदात्मक कार्यों आदि के कारण काम करने की स्थिति, मज़दूरी और मजदूरी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है जिससे राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। □ – बिश्वजीत देब

उम्मीद

फासीवाद का बुलडोज़र
चल रहा था ....
धर्म की पहचान कर,
धर्म के ही नाम पर,
शासन के काम पर,
संविधान को तज कर,
न्यायादेश को धत्ता बताकर,
जन पर और उसके घर पर ....

मुख्य मीडिया मस्त था,
सीधा प्रसारण में व्यस्त था,
योगी मॉडल गुनगुना रहा था,
विज्ञापनों का चेक भुना रहा था,
बुलडोज़र की महत्ता जारी थी,
टीवी पर वोटिंग जारी थी,
लोगों की नज़रें टीवी पर थी,
घर–दीवारें धड़ाधड़ गिर रही थी।

अचानक सब थम गया,
वो बुल्डोज़र,
जहां जैसे था, जम गया,
"बस एक इंच भी आगे नहीं"
ये है न्यायादेश,
थमो वहीं,
सामने "वो" एक नया आग़ाज़ थी,
वो वृंदा नहीं,
मजलुमों के आवाज़ थी,
उस एक आग़ाज़ से,
जुल्म–ज़ालिम थम गया,
जो हम आवाज़ मिला दें,
तो सोचो, जुल्म–ज़ालिम दोनों गया।

...दुनिया के मेहनतकशों, एक हो...

– अमल पांडेय

कार्ल मार्क्स के 205 वीं जयंती

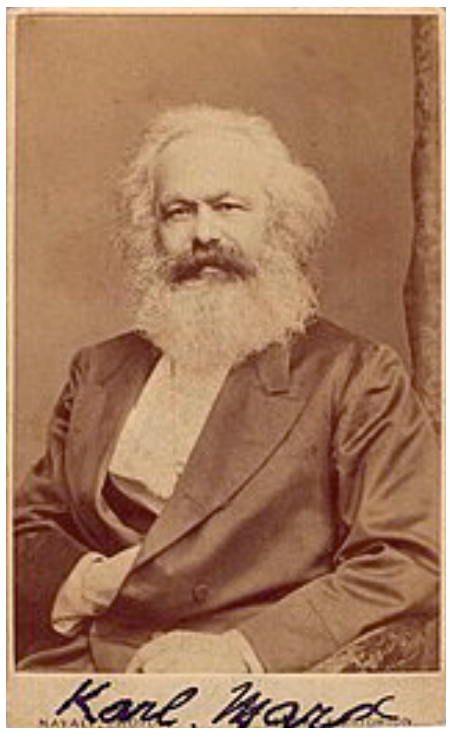

5 मई की शाम को सीपीएम पार्टी कार्यालय के सभागार में कॉ0 सुरजीत सिंहा की अध्यक्षता में कार्ल मार्क्स की 205 वीं जयंती पर एक सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता कॉ0 समीर दास ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी मार्क्स के विचार व सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने समाज की व्याख्या मात्र की है, किन्तु उसे बदलने का सिद्धांत मार्क्स ने ही दिया। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में प्रकाश स्तंभ है। दुनिया में शोषण मुक्त समाज की स्थापना मार्क्स के विचारों के साथ ही किया जा सकता है। मार्क्स ने कहा था कि श्रमिकों के पास खोने के लिये सिर्फ गुलामी की जंजीरे हैं, लेकिन हासिल करने के लिए सारी दुनिया पड़ी है।

आज की परिस्थिति में धर्म पर मार्क्स की साफ़गोई को समझने की सख्त ज़रूरत है।

मार्क्स ने धर्म के बारे में लिखा है, ''अधार्मिक आलोचना का आधार है: मनुष्य धर्म की रचना करता है, धर्म मनुष्य की रचना नहीं करता है। धर्म मनुष्य की स्व–चेतनता और स्व–प्रतिष्ठा है, ऐसे मनुष्य की, जो अभी तक अपने आपको जान नहीं पाया है, या फिर भटक गया है।

धार्मिक व्यथा, एक साथ वास्तविक व्यथा की अभिव्यक्ति तथा वास्तविक व्यथा का प्रतिवाद दोनों है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन संसार का हृदय है, ठीक उसी तरह जैसे वह भावविहीन परिस्थितियों की भावना है। वह जनता के लिए अफीम है। जनता के भ्रामक सुख के रूप में धर्म के उन्मूलन का अर्थ है उसके वास्तविक सुख की माँग करना। मौजूदा हालात के संबंध में भ्रमों का परित्याग करने की माँग उन हालात के परित्याग की माँग करती है जिनके लिए भ्रम जरूरी बन जाते हैं। अतः, धर्म की आलोचना भ्रूण रूप में आँसुओं की घाटी, धर्म जिसका प्रभामंडल है, की आलोचना है। यानी धर्म के अंत की शर्त है वास्तविक सुखों की सृष्टि, जब तक वास्तविक सुख पैदा नहीं कर पाते तब तक धर्म रहेगा, आम लोगों के दुख रहेंगे और आंसू भी रहेंगे।

1855–56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संताल हूल (विद्रोह) को मार्क्स ने भारतीय जनता का पहला जन–विद्रोह कहा था। □

झारखंड साइंस फोरम का राज्य सम्मेलन

आज जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, राँची के दयानंद ऑडिटोरियम में झारखंड साइंस फोरम का पहला राज्य सम्मेलन 24 अप्रैल को सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष प्रो0 रमेश शरण ने सम्मेलन की शुरुआत की। सचिव प्रो0 शिशिर कुमार फोरम ने विगत वर्ष के कार्यों का विवरण पेश किया। सम्मेलन में आने वाले वर्ष के लिए मुख्य ज़ोर ''वैज्ञानिक चेतना'' के व्यापक विस्तार पर केंद्रित रहा। सम्मेलन में नई बारह सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष–प्रो0 रमेश शरण, उपाध्यक्ष–प्रो0 शिशिर कुमार, सचिव–सुभाष चटर्जी, संयुक्त सचिव– रवि कुमार, एस0 रमेश, जगदीप उरांव और कोषाध्यक्ष–किशोर चक्रबर्ती और अन्य शामिल हैं। □

साझा मंच, झारखंड (समझ) का विस्तार

साझा मंच, झारखंड द्वारा सद्भावना और एकता के लिए पिछले दिनों विभिन्न समुदायों के साथ कई कार्यक्रम करने के बाद मंच का विस्तार करने के लिए रविवार, 29 मई को दूसरी बैठक हुई बैठक जिसमें सर्वसम्मति से अशोक वर्मा (प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता), जय सिंह यादव (महावीर मंडल), फादर टोनी (बगईचा), इबरार अहमद (अंजुमन इस्लामिया) तथा सरदार हरमिंदर बीर सिंह (गुरुद्वारा प्रबंधक समिति) को मिलाकर पाँच सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया। एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया जिसमें प्रकाश विप्लव (माकपा), शुभेंदु सेन (भाकपा माले), अजय सिंह (भाकपा), संजीव सिन्हा (कांग्रेस) तथा जीत गुप्ता (झामुमो) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंच की कोर कमेटी का भी गठन हुआ।

साझा मंच झारखंड के गठन का उद्देश्य नफ़रत की राजनीति के कारण धर्म के आधार पर समाज के विभाजन की साजिश को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और सद्भाव से जवाब देना है। बैठक में मॉब लिंचिंग निषेध कानून को अविलंब लागू करने की मांग की गई। मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल कर झारखंड में बढ़ रहे सांप्रदायिक वारदातों को रोकने के लिए ठोस सुझाव देगा। बैठक में सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रांची महानगर के सभी वार्डों में कार्यक्रम आयोजित करने तथा जुलाई में एक बड़ा कन्वेंशन करने का निर्णय लिया गया। इसी सिलसिले में 15 जून को रातू रोड में अगली बैठक रखी गई है। झारखंड के सभी जिलों में साझा मंच झारखंड का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। □

– सुधांशु शेखर

सीटू का 53 वाँ स्थापना दिवस

झारखंड समेत पूरे देश में सीटू के 53वें स्थापना दिवस 30 मई को बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। एकता और संघर्ष के साथ सीटू आज देश के मजदूर आंदोलन का अगुवाई करने वाला महत्वपूर्ण श्रमिक संगठन है। सीटू के पास श्रमिक आंदोलन के एक शताब्दी से ज्यादा की विरासत और अनुभव है। सीटू राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने अपने सम्बोधन में कहा कि सीटू ने ही मजदूर आंदोलन में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्ष की शुरुआत करते हुए कई संयुक्त अखिल भारतीय हड़तालों का सफल आयोजन किया। सीटू हमेशा से ट्रेड युनियनों की व्यापक एकता की पक्षधर रही है और सभी ट्रेड युनियनों का एक संयुक्त महासंघ बनाए जाने की वकालत करती रही है। आज जब कार्पोरेट परस्त सरकार देश की संपदा को निजी हाथों में सौंपने और मजदूरों को धर्म के नाम पर विभाजित करने का षडयंत्र रच रही है ऐसे समय में मजदूर वर्ग की व्यापक एकता और संघर्ष ही इस षडयंत्र को पराजित कर सकती है।

झारखंड में सीटू के स्थापना दिवस का आयोजन सभी औधोगिक क्षेत्रों मे किया गया। □

देश और देशवासी : आंकड़ों में

पिछले साल, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.7% रही। बेशक देश के लिए बहुत गर्व की बात है।

अब इसी देश के देशवासियों की स्थिति पर नवीनतम आँकड़े पेश करते हैं, जो देश के आँकड़ों के बिलकुल विपरीत है।

मानव विकास सूचकांक : विश्व में 131वाँ स्थान; ग्लोबल हंगर इंडेक्स : 116 देशों में 101वाँ; खाद्य सुरक्षा सूचकांक : 113 देशों में 71वाँ; महिला, शांति व सुरक्षा सूचकांक : 170 देशों में 148वाँ; ग़रीबी : 109 देशों में 66वाँ; प्रति व्यक्ति जीडीपी : 194 देशों में 144वाँ; प्रति व्यक्ति आय : विश्व में 128वाँ और एशिया में 33वाँ; खुशी सूचकांक : 146 देशों में 136वाँ; भ्रष्टतम देशों की सूची में 85वाँ; प्रेस स्वतंत्रता : विश्व में 150वाँ स्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, आदि सब में फिसड्डी।

अर्थात्, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसकी जीडीपी वृद्धि रफ़्तार विश्व में सबसे तेज है। आम जन के विकास के ऐसे विभत्स आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि कोरपोरेट–अमीरों और मेहनतकश जनता के बीच की खाई तेजी से बढ़ती जा रही है। श्रम–पोर्टल के नवीनतम आँकड़े, जिनमें 24 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मज़दूर निर्बंधित हैं, बताते हैं कि उनमें से 94% की आय 10 हज़ार रुपए से भी कम है। भारत में असमानता के स्तर पर नवीनतम रिपोर्ट इंगित करती है कि 25 हज़ार प्रति माह पाने वाला व्यक्ति देश के 10% सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों में शामिल हैं। ऑक्सफेम के रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। एक प्रतिशत अमीरों के पास देश की आय का लगभग 73% हिस्सा जाता है। इससे अमीरों के संख्या तेजी से बढ़ रही है और उससे भी कई गुणा ज़्यादा तेजी से बड़ी संख्या में लोग ग़रीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं, जिससे मूलभूत ज़रूरतें भी उनकी पहुँच से दूर हो गई है। एक चिंताजनक आँकड़ा यह भी है कि बरोजगारी दर शिक्षितों में काफ़ी ज़्यादा है।

देश पर गर्व करने वाले देशवासियों पर भी कुछ रहम करें... और देशवासी भी अपनी बदहाली से निकलने के लिए एकजुट होकर असली जनमुद्दों पर संघर्ष करें। □

– अमल पाण्डेय

एसएफआई की पहल

शिक्षा और छात्रों के ज्वलंत मुद्दे – शिक्षकों की कमी, नई शिक्षा नीति के कुप्रभाव, लगातार महँगी होती शिक्षा, छात्र संघ का चुनाव समय पर न होना आदि पर एसएफआई स्कूल–कॉलेजों में छात्रों से लगातार सम्पर्क में है।

एसएफआई झारखंड ने अब तक 3 जिलों – पाकुड़, दुमका और कोडरमा में बैठक कर वहाँ तदर्थ कमिटियों का गठन किया है। □

किसानों की बदहाली

झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि और खान–खनिज पर निर्भर है। झारखण्ड में किसानों के पिछड़ेपन के पाँच मुख्य कारण हैं – सिंचाई की व्यवस्था का अभाव, उत्पाद यानि जिन्सों के लिए बाजार का अभाव, समय पर ऋण का नहीं मिलना, काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से खेत मजदूरों और नौजवानों का पलायन तथा कृषि में सरकारी निवेश की भारी कमी।

कई इलाकों के बदहाल किसान महाजनी कर्ज के जाल में फंस कर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं।

वनों की कटाई और बदलते परिवेश ने पशुधन को भी कम कर दिया है। उर्वरकों की बढ़ती कीमत और उसकी कालाबाजारी ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। कीटनाशक दवाइयों का भी यही हाल है।

पहले रघुवर और अब हेमन्त सरकार दिल्ली में पूंजीपतियों को न्यौता देकर आर्थिक समृद्धि तलाश रही है। लैंड पुलिंग के नाम पर आदिवासियों की जमीन बड़े–बड़े कॉरपोरेटों को दी जा रही है। भूमि सुधार नहीं होने के कारण झारखण्ड में लगभग 2 लाख भूमिहीन हैं, 22 हजार खेत मजदूर और 18 हजार बटाईदार।

सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के बिना वर्षा पर निर्भर रहकर कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता। न पारम्परिक खेती और ना ही आधुनिक–वैज्ञानिक खेती हो सकती है। राज्य में कुल कृषि भूमि का सिर्फ़ 5 प्रतिशत हिस्से में ही सिंचाई की व्यवस्था है।

झारखण्ड के किसानों की प्रतिमाह आय 5000 रूपए है, जो कि विश्व बैंक के पैमाने (165 रूपये प्रति दिन) के अनुसार किसानों की स्थिति अति गरीब की श्रेणी से भी नीचे है। सरकारी बैंकों से 10% किसानों को ही कर्ज मिलता है और शेष किसान महाजनों से कर्जा लेते हैं।

झारखण्ड में एमएसपी के तहत राशि की भुगतान में धान क्रय केन्द्र में घोटाला किया गया। पलामू, गढ़वा और चतरा में जांच चल रही है। 20–21 में 60 लाख टन धान का उत्पादन हुआ। 63.85 लाख टन की निर्धारित ख़रीद लक्ष्य की जगह एसएफसीआई और एसएफसीआई ने किसानों से सिर्फ़ 4.5 लाख टन धान की ख़रीद की। बाक़ी धान की खरीद दलाल, विचौलिया, महाजन एवं व्यापारी लोग करते हैं। किसानों की सूची बनाकर उन्हें सिर्फ 900 से 1200 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान करते हैं उसी धान को वे लैम्पस और पैक्स को सरकारी मूल्य 2060 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बेचते हैं।

झारखण्ड सरकार ने लाखों एकड़ गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना बंद कर दिया है। □

– सुरजीत सिन्हा

कोविड और डिजिटल शिक्षा

ज्ञान–विज्ञान समिति द्वारा झारखंड के 20 ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों के 197 पंचायतों में 31 मार्च से 7 अप्रैल तक ''झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर डिजिटल शिक्षा पर प्रभाव और पहुँच'' विषय पर हुए जन सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 84% घरों में DTH नहीं हैं, 97.1% बच्चे DTH के माध्यम से पढ़ाई नहीं करते हैं। 97% बच्चों के पास स्मार्ट फ़ोन नहीं थे, 87.3% अभिभावकों का कहना था कि कोविड के कारण पिछले दो वर्षों में बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई। 97% अभिभावकों का कहना था कि सरकार को इस भरपाई के लिए विशेष उपाय करने चाहिए।

8774 लोगों के बीच किया गया ये सर्वे, सरकार के डिजिटल शिक्षा मिशन की पोल खोलता है। 12% इंटर्नेट कनेक्टिविटी और ज़बरदस्त ग़रीबी के बीच बड़े–बड़े सरकारी दावों का ये सर्वे पर्दाफ़ाश करता है। □

डीवाईएफआई का राज्य सम्मेलन

धनबाद – बेरोजगारी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान के साथ भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई) का 5 वाँ राज्य सम्मेलन 27 अप्रैल को नेहरू सामुदायिक केन्द्र,धनबाद में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता चार सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने किया।उदघाटन सत्र की सम्बोधित करते हुए डीवाईएफआई के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हिमांगराज भट्टाचार्य ने कहा कि देश में युवा वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार रोजगार ही छिन रही है। सरकारी सम्पत्तियों को बेचा जा रहा है और देश को गुलाम बनाया जा रहा है। युवाओं का भविष्य खतरे में है। एक नए भारत का निर्माण के लिए युवाओं को भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। निवर्तमान राज्य सचिव संजय पासवान ने राजनीतिक सांगठनिक रिपोर्ट पेश किया। सर्वसम्मति से 21 सदस्यीय नयी राज्य कमिटी का चुनाव किया गया जिसमें सुरेश मुण्डा अध्यक्ष, संतोष कुमार चौधरी महासचिव, कपिल महतो कोषाध्यक्ष शामिल हैं। □

एआईसीडब्लूएफ की कार्यकारिणी बैठक

आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन की वर्किंग कमिटी की बैठक सीएमपीडीआई, रांची में संपन्न हुई। कोल इंडिया के रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर अनुषांगी और ग़ैर–अनुषांगी कम्पनियों के आसन्न विनिवेश और मज़दूर विरोधी नीतियों के विरोध में आगामी 15 जून से 14 जुलाई तक माह भर के अखिल भारतीय व्यापक संघर्ष का कार्यक्रम तय हुआ। लम्बित वेतन समझौता और कोल मज़दूरों की माँग को जोड़ कर व्यापक एकता बनाकर हड़ताल का भी निर्णय हुआ है।

बैठक में कॉ. बासुदेव आचार्य अध्यक्ष और सीटू के अखिल भारतीय महासचिव कॉ. तपन सेन भी मौजूद थे □

लोहरदगा साइंस फिल्म फेस्टिवल

साइंस फॉर सोसायटी, झारखंड एवं वैज्ञानिक चेतना (साइंस वेब पोर्टल), जमशेदपुर द्वारा जन–जन तक विज्ञान पहुंचाने, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं लोकतांत्रिक चेतना के विकास एवं विस्तार के लिए लोहरदगा (झारखंड) में 29–30 अप्रैल एवं 1 मई 2022 को पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। जिसमें मुख्य रूप से डाक्यूमेंट्री, एनीमेशन एवं शार्ट फिल्में दिखाई गई। उक्त तीन दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न फ़िल्मकारों की जन मुद्दों पर आधारित झारखंड के 13 फ़िल्मों सहित देश के विभिन्न राज्यों की करीब 10 भाषाओं की कुल 40 से अधिक फिल्में दिखाई गई।

फेस्टिवल में स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया जबकि वहां झारखंड की सांस्कृतिक विरासत आधारित फिल्मों का भी प्रदर्शन हुआ।

उल्लेखनीय है कि साइंस फार सोसायटी, झारखंड ने आजादी के 75 वें वर्ष को, डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की स्मृति में, 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्ष' के रूप में मनाने एवं मुद्दा आधारित फिल्मों को जन जागरूकता का माध्यम बनाने का निर्णय किया है। इसके तहत पहले चरण में झारखंड की सभी पांच कमिश्नरियों में एक एक साइंस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय लिया गया है , जिसे बाद में विभिन्न जिलों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की योजना है ताकि राज्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास एवं विस्तार के लिए जन संवाद तथा जन विज्ञान अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। लोहरदगा साइंस फिल्म फेस्टिवल की सफलता ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। □

मई दिवस

1 मई को झारखंड के 24 जिलों में लगभग 294 स्थानों पर सीटू व अन्य सहयोगी संगठनों के बैनर तले सभी मजदूरों व कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मई दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर किया। भारत में मई दिवस के शुरुआत का शताब्दी समारोह भी आज से शुरू हो गए जो पूरे साल चलेगा। उल्लेखनीय है कि 1 मई 1923 को ही मद्रास शहर के मरीना बीच पर मजदूर नेता एम सिंगारवेलू ने लाल झंडा फहरा कर भारत में मई दिवस की शुरुआत की थी। विस्तृत खबर अगले पेज पर। □

मांडर उपचुनाव

विधानभवन उप चुनाव में माँडर (अजजा) सीट से माकपा ने राज्य कमिटी सदस्य सुभाष मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। शनिवार 4 जून 2022 को उन्होंने पर्चा भरा। चुनाव 23 जून को होगा और नतीजा 26 जून को आएगा। इंडियन नेशनल लीग ने इस चुनाव में बिना शर्त समर्थन दिया है। □

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न

इस चुनाव में ग्रामीण जनता की भागीदारी बढ़ी और विशेष कर महिलाओं ने चुनावी प्रक्रिया में काफी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस बार के पंचायत चुनाव में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है। अब तक प्राप्त नतीजों के अनुसार हमारे सदस्यों और समर्थकों ने जिला परिषद की 2 पंचायत समिति की 32 मुखिया की 29 और वार्ड सदस्यों की 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है।

कहने को चुनाव गैर दलीय आधार पर हुआ है, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख के प्रभावी पदों को हथियाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी भाजपा–आजसू गठबंधन ने अपने आदमी को बैठाने के लिए जन–प्रतिनिधियों की खरीद–विक्री का खेल शुरु कर दिया है। हमारे लिए निर्वाचित पंचायतें वर्ग संघर्ष का औजार हैं। झारखंड में पंचायती राज के पिछले दो कार्यकालों का अनुभव बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के माध्यम से पंचायतों पर अधिकार होने के बावजूद इलाके के सामंती और निहित स्वार्थी तत्व भष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से वंचित तबकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का ही काम करते रहे। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सरकारी एजेंसी के रुप में इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की अपने क्षेत्र के विकास में सीधी भागीदारी नहीं हो सकी। □

मॉब लिंचिंग पर मुख्यमंत्री को पत्र

प्रिय मुख्यमंत्री जी,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित उपरोक्त विधेयक को माननीय राज्यपाल ने तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ सामान्य तब्दीली के लिये पुर्नविचार हेतु राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। इस संबंध में हमारी पार्टी की समझ है कि इस विधेयक में लिंचिंग की परिभाषा में कोई त्रुटि नहीं है। साथ ही लिंचिंग को सिर्फ आपराधिक या शारीरिक यातना तक सीमित करने से इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक दुष्परिणाम हो सकते हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि इस विधेयक में अनुवाद संबंधी यदि कुछ तकनीकी त्रुटियां है तो उसे ठीक कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिये राजभवन शीघ्र भेजे जाने का कष्ट किया जाय क्योंकि इस विधेयक के कानून बनने में विलंब होने से राज्य में शांति और सदभाव को नुकसान होगा और विभाजनकारी षड्यंत्रकारियों को बल मिलेगा। यदि इस संबंध में आप वामदलों समेत अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से विचार–विमर्श करना चाहते हैं तो आग्रह है कि जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस विधेयक के पक्ष में चर्चा करा ली जाय।

विश्वासभाजन
(प्रकाश विप्लव)
राज्य सचिव

जिलों से आंदोलन की तस्वीरें

सिन्दरी

धनबाद

गोमिया

रांची

सिन्दरी

कोडरमा

जलेस राज्य सम्मेलन, जमशेदपुर

कोडरमा

पूर्वी सिंहभूम

मई दिवस, रांची

वामदलों का महंगाई के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन, रांची

पार्टी कोष में सहयोग

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संकलन एवं संयोजन अमल पाण्डेय व बिपिन कु0 सिन्हा। अधिक जानकारी एवं सुझाव के लिये सम्पर्क करें– माकपा पार्टी कार्यालय, विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com